1. श्री पी. वी. बेंकटसुबहमणियम,
भूतपूर्व विधि सचिव,
भारत सरकार
—अध्यक्ष

2. संयुक्त सचिव,
कॉपीराइट प्रभारी,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
शिक्षा विभाग
—पदेन सदस्य

3. संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार,
विधि एवं न्याय मंत्रालय
(विधि कार्य विभाग)
भारत सरकार
—पदेन सदस्य

4. विधि सचिव,
तमिलनाडु सरकार
—पदेन सदस्य

5. विधि सचिव,
बिहार सरकार
—पदेन सदस्य

6. विधि सचिव,
केरल सरकार
—पदेन सदस्य

7. विधि सचिव
विधि एवं संसदीय कार्य विभाग
मेघालय सरकार
—पदेन सदस्य

8. सचिव
विधि विभाग
गुजरात सरकार
—पदेन सदस्य

9. विधि सचिव
जम्मू एवं कश्मीर सरकार
—पदेन सदस्य

(ख) और (ग) कॉपीराइट बोर्ड का अभी पुनर्गठन किया जाना है। कॉपीराइट (संशोधन) अधिनियम, 1994 के द्वारा कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के संशोधन के परिणामस्वरूप कॉपीराइट नियमावली तैयार की जा रही है और इसके शीघ्र बाद कॉपीराइट बोर्ड का पुनर्गठन किया जाएगा।

(घ) वर्ष 1990-91 में कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 19 क के अन्तर्गत कॉपीराइट बोर्ड के पास दो याचिकाएं दायर की गई थी और दोनों याचिकाओं पर निर्णय दे दिया गया—एक सितम्बर, 1990 में और दूसरा अक्तूबर, 1991 में।

धारा 19 क के अन्तर्गत कुल 11 याचिकाएं लम्बित हैं जिन पर बोर्ड को निर्णय देना है। इन याचिकाओं के ब्यौरे तथा इनके लम्बित होने के कारण संलग्न विवरण में दिए गए हैं। (नीचे देखिए)।

(ङ) कॉपीराइट कार्यालय के लिए कोई पृथक बजट नहीं है क्योंकि यह कार्यालय शिक्षा विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन है और कॉपीराइट कार्यालय के सम्पूर्ण कर्मचारियों को इस विभाग के कर्मचारियों के साथ रखा गया है जहां तक कॉपीराइट बोर्ड का संबंध है अध्यक्ष के लिए मानदेय एवं कार्यालय व्यय के लिए अध्यक्ष के टी. ए./डी. ए. के लिए बोर्ड की बैठकों में शामिल होने के लिए सदस्यों को दिए जाने वाले मानदेय के लिए तथा आकस्मिक व्यय के लिए वर्ष 1993-94 के दौरान कुल 82,663 रु. की राशि खर्च की गई।

25 और 26 नवम्बर, 1992 को भोपाल में आयोजित बोर्ड की बैठक पर कुल 10,194 रु. खर्च किए गए। बोर्ड के पास रखी गई 25 याचिकाओं में से 16 याचिकाओं पर निर्णय दे दिया गया।

विवरण

कॉपीराइट बोर्ड के समक्ष लंबित याचिकाएं

(कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 19 क के अंतर्गत)

क्रम संख्या	मामला संख्या	कब से लम्बित है	लंबित होने के कारण
1	60/85 (उत्तर पूर्वी क्षेत्र)	1985	मामला दो बार स्थगित हुआ— प्रथमतः दोनों पक्षकारों की सहमति से द्वितीयतः सरकार द्वारा अवकाश घोषित करने के कारण ।
2	7/87 (उत्तर पूर्वी क्षेत्र)	1987	मामले को पूर्ण दस्तावेजों के अभाव में बोर्ड के समक्ष सूचीबद्ध नहीं किया जा सका ।
3	18/91 (मध्य क्षेत्र)	1991	दोनों पक्षकारों में से किसी पक्षकार के भी उपस्थित नहीं होने के कारण मामला स्थगित कर दिया गया ।
4	3/92 (मध्य क्षेत्र)	1992	याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादियों की लेखा बहियों की जांच करने के कारण मामला स्थगित ।
5	13/92 (पूर्वी क्षेत्र)	1992	पूर्ण दस्तावेजों के अभाव में बोर्ड के समक्ष मामले को सूचीबद्ध नहीं किया जा सका ।
6	9/93 (उत्तरी क्षेत्र)	1993	दोनों पक्षकारों द्वारा दस्तावेजों को पूरा करने के लिये मामला स्थगित कर दिया गया ।
7	1/94 (दक्षिणी क्षेत्र)	1994	वर्ष 1994 में कॉपीराइट बोर्ड की कोई बैठक नहीं हुई । पिछले बोर्ड का कार्यकाल दिनांक 31-3-94 को समाप्त हो गया था ।
8	5/94 (उत्तरी क्षेत्र)	1994	–वही–
9	6/94 (उत्तरी क्षेत्र)	1994	–वही–
10	7/94 (उत्तरी क्षेत्र)	1994	–वही–
11	17/94 (पश्चिमी क्षेत्र)	1994	–वही–

Cconference of Education in Islamabad

1555. SHRI RAMDAS AGAR'.'. Will the :' HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(3) Whether he visited Pakistan recently as Leader of the Indian Delegation top?.; in the 12th Commo Ministers, Conference held in as reported in the Hindustan Times 25th November, 1994;

(b) If so, what was the agenda of the Conference; and

(c) What was the outcome of discussion*/ recommendations made at the Conference particularly on the "role of the State in Education ?".

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KUMARI SELJA) : (a) The Minister for Human Resource D.a delega-tion to represent Indi!th Conferenceof Commonwealth Education Ministers held at Islamabad on 27 November to 1 December 1994.

(b) The main theme of the Conference was "The Changing Role of the State in Education, Politics and Partnerships." The Agenda of the the Conference included discussions on the main theme and Round tables on various aspects of education.

(c) The outcome of the discussions was issued in the form of a Communique which inter alia stated that "The State must continue to retain a central responsibility for ensuring access, quality control, transparency, accountability and equity, it remained responsible for providing Basic Education as a right to all citizens." The Ministers also noted that partnerships and participation in education had recently assumed special significance as a result of the spread of principle of democracy and its values, a reassessment of the role of the State in society, and expanding demands in the States in the face of fiscal constraints.

Financial Assistance to Voluntary Cultural Organisations

1556. SHRIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) the number of voluntary cultural organisations of Gujarat and Maharashtra being financially assisted for the dissemination of tribal folk art and culture;

(b) the details of financial assistance given to them during each of the last tare i

(c) the number of applications received for financial assistance and the latest position in regard to the consideration of the pending applications ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KUMARI SELJA) : (a) Three voluntary organisations from Gujarat and two voluntary organisations from Maharashtra have been financially assisted during the last three year under the scheme of Financial Assistance for Promotion and Dissemination of Tribal and Folk Art and Culture.

(b) The detailed information regarding financial assistance given to voluntary organisations during each of the last three years District-wise is as per annexer as Statement. *(See* below).

(c) 9 applications were received from Gujarat and Maharashtra during the last three years, none of which is pending.

Statement

Financial Assistance to Voluntary Cultural Organisations

Sl. No.	Name of the State	Name of District	No. of Organisations	Financial Assistance Given		
				1991-92	1992-93	1993-94
				Rs.	Rs.	Rs.
1	Gujarat	Ahmedabad	3	60,000	1,00,000	80,000
2	Maharashtra	Bombay	2	Nil.	1,40,000	60,000

CBSE Schools in Karnataka

1557. SHRI K. RAHMAN KHAN : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) how many Central Board of Secondary Education (CBSE) Schools are functioning in Karnataka;

(b) what are the criteria laid down by Government for according permission to start a CBSE School;

(c) the number of CBSE Schools sanctioned in Karnataka during the years 1992-93, 1993-94 and so far in 1994-95 with names of such Schools and the names of places, and

(d) in how many cases, the Schools have been sanctioned without getting No Objection Certificate from Government of Karnataka ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KUMARI SELJA) : (a) As per information received from the Central Board of Secondary Education (CBSE), 91 schools of Karnataka are affiliated to the CBSE as on 30-11-1994.

(b) The Schools seeking affiliation to the CBSE are required to fulfil various conditions prescribed in the Affiliation Bye-laws of the Board. Formal recognition of the school and issue of a'No Objection Certificate